



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2018/ माघ 23, 1939

No. 61]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2018/MAGHA 23, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2018

परिवर्चना रोधी जाँच

**विषय : सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2016-सीमाशुल्क, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से "ग्लास फाइबर" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के कथित परिवर्चना से संबंधित परिवर्चना रोधी जाँच की शुरुआत**

**सं. 7/25/2017-डीजीएडी.**— समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

2. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है), ने 6 जुलाई, 2016 की अपनी अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 15/10/2015-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच में चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय ने दिनांक 1 सितम्बर, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

3. यतः, पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ 1975 की धारा 9क के अनुसार, मै. ओवन्स-कार्निंग (इंडिया) प्रा. लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता या घरेलू उद्योग कहा गया है), जो भारत में ग्लास फाइबर के प्रमुख विनिर्माता हैं, ने प्राधिकारी के समक्ष यह आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की है कि ग्लास फाइबर जो दिनांक 1 सितम्बर, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2016- सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क के अधीन है, को अब भारत में धोखे से आयात किया जा रहा है। एशिया कंपोजिट

मैटेरियल्स (थाइलैंड) कं. लि. चीन से आयातित ग्लास रोविंग (एआर, ग्लास फाइबर का एक रूप) से ग्लास चाण्ड स्ट्रेंड्स मैट्स (सीएसएमएस, संबद्ध वस्तु का एक रूप) का उत्पादन करती है और उसके बाद चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर पर लागू पाटनरोधी शुल्क की परिवंचना के लिए भारत को उसका निर्यात करती है।

#### **विचाराधीन उत्पाद**

4. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) एशिया कंपोजिट मैटेरियल्स (थाइलैंड) कं. लि., थाइलैंड द्वारा उत्पादित चाण्ड स्ट्रेंड्स मैट्स (सीएसएमएस) है।

#### **मौजूदा उपाय**

5. वर्तमान में लागू उपाय और जिन्हें कथित रूप से प्रवंचित किया जा रहा है, वित्त मंत्रालय द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के आयातों पर दिनांक 1 सितम्बर, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लागू किए गए पाटनरोधी उपाय हैं।

#### **जाँच शुरुआत के आधार**

6. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के आयातों पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क की परिवंचना 4 मार्च, 2011 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 30/2011-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा ग्लास फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद शुरू हुई। यह परिवंचना "उत्पाद और देश परिवंचन" की श्रेणी में अधीन आती है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि सिचुआन वाइबो न्यू मैटेरियल ग्रुप कं. लि. (चीन) की एक शाखा एशिया कंपोजिट मैटेरियल्स (थाइलैंड) कं. लि. की स्थापना चीन जन. गण. से ग्लास फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के तुरंत बाद 2012 में की गई। एशिया कंपोजिट मैटेरियल्स (थाइलैंड) कं. लि. चीन से आयातित ग्लास रोविंग (एआर, ग्लास फाइबर का ही एक रूप) से ग्लास चाण्ड स्ट्रेंड्स मैट्स (सीएसएमएस, संबद्ध वस्तु का एक रूप) का उत्पादन करती है और उसके बाद भारत को उसका निर्यात करती है। एशिया कंपोजिट मैटेरियल्स (थाइलैंड) कं. लि. थाइलैंड में एकमात्र ग्लास फाइबर चाण्ड स्ट्रेंड मैट इकाई है और उसके पास थाइलैंड में पूर्ण क्षमता की उत्पादन सुविधा नहीं है। सीएसएमएस ग्लास फाइबर जिसमें दूसरे स्तर का प्रसंस्करण अपेक्षित होता है की केवल एक उप-किस्म है। ग्लास फाइबर की अन्य उप-किस्म जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, में दो स्तर का प्रसंस्करण नहीं होता है। इस प्रकार, सीएसएमएस एकमात्र उत्पाद है जिसका थाइलैंड में प्रसंस्करण और भारत को निर्यात किया जा सकता है। संबंधित निर्यातक की वेबसाइट स्वयं पाटनरोधी शुल्क की परिवंचना को प्रोत्साहित करती है। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से भारत में थाइलैंड से सीएसएमएस के आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है और चीन से कम हुई है। इसके अलावा चीन से थाइलैंड को रोविंग के निर्यातों में वृद्धि हुई है जिससे स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के बाद व्यापार की प्रवृत्ति में परिवर्तन दर्शाता है। इस परिवंचना से संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव भी निष्क्रिय हो गए हैं। संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी घरेलू उद्योग को एशिया कंपोजिट मैटेरियल्स (थाइलैंड) कं. लि. द्वारा उत्पादित चाण्ड स्ट्रेंड्स मैट्स (सीएसएमएस) के आयातों के जरिए पाटनरोधी शुल्क की परिवंचना के कारण क्षति होना जारी है।

#### **प्रक्रिया**

7. संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में परिवंचना रोधी जाँच की आवश्यकता को साक्ष्यांकित करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार से स्वयं को संतुष्ट करते के पश्चात् प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(1क) के अनुसार 1 सितम्बर, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की कथित परिवंचना की परिवंचना रोधी जाँच शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं ताकि इस बात की जाँच की जा सके कि क्या एशिया कंपोजिट मैटेरियल्स (थाइलैंड) कं. लि., थाइलैंड द्वारा उत्पादित चाण्ड स्ट्रेंड मैट (सीएसएमएस) के आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं और क्या उनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और क्या एशिया कंपोजिट मैटेरियल्स (थाइलैंड) कं. लि., थाइलैंड द्वारा उत्पादित चाण्ड स्ट्रेंड मैट (सीएसएमएस) के आयातों पर 1 सितम्बर, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने की आवश्यकता है।

8. इस परिवंचना जाँच में शामिल देश थाइलैंड है।

9. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) अप्रैल 2016-मार्च 2017 तक की है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2013-मार्च 2014, अप्रैल 2014-मार्च 2015, अप्रैल 2015-मार्च 2016 और जाँच अवधि की अवधि शामिल होगी।

**सूचना प्रस्तुत करना**

10. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जाएगा ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत कर सकें:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी****पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय****वाणिज्य विभाग, जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,****5, संसद मार्ग,****नई दिल्ली-110001**

11. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**समय-सीमा**

12. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के शुरुआत से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

13. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की अधिसूचना से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

14. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

15. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियाँ पांच-पांच (5-5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

16. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

17. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशिकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

18. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

19. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

20. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### **असहयोग**

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी

## **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Revenue)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi the 12th February, 2018

(Anti-Circumvention Investigation)

**Subject : Initiation of anti-circumvention investigation concerning the alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on the imports of “Glass Fibre”, originating and exported from China PR vide Customs Notification No. 48/2016-Customs dated 1st September, 2016.**

**No.7/25/2017-DGAD.—** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof (hereinafter referred to as the Rules or AD Rules),

2. Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in a sunset review investigation, vide its Final Findings Notification No. 15/10/2015-DGAD. dated 6<sup>th</sup> July, 2016, had recommended the imposition of anti-dumping duty on the imports of Glass Fibre originating in or exported from China PR, and the Ministry of Finance, vide Customs Notification No. 48/2016-Customs (ADD). dated 1<sup>st</sup> September, 2016, had imposed the anti-dumping duty on the imports of Glass Fibre, originating in or exported from China PR.
3. Whereas, in terms of the Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, read with Rule 25 of the Anti-Dumping Rules, M/s Owens-Corning (India) Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the Petitioner or the Domestic Industry), a major manufacturer of Glass Fibre in India, has filed a petition before the Authority alleging that Glass Fibre, which is the product subject to anti-dumping duty vide Customs Notification No. 48/2016-Customs (ADD), dated 1<sup>st</sup> September, 2016, is now being circumvented into India. Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd produce glass chopped strands mats (CSM, a form of subject goods) from glass roving (AR, also a form of glass fibre) imported from China and then export it to India to circumvent the anti-dumping duty imposed on the imports of Glass Fibre, originating in or exported from China PR.

### **Product Under Consideration**

4. The product under consideration (PUC) in the present petition is “Chopped Strand Mat (CSM) produced by Asia Composite Materials (Thailand) Co, Thailand”.

### **Existing Measures**

5. The measures currently in force and which are allegedly being circumvented are the anti-dumping measures imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 48/2016-Customs (ADD), dated 1<sup>st</sup> September, 2016 on the imports of Glass Fibre, originating in or exported from China PR.

### **Grounds for Initiation**

6. The Petitioner claims that the circumvention of the anti-dumping duty levied on the imports of glass fibre originating in or exported from the subject country started after the imposition of anti-dumping duty on the imports of Glass Fibre vide Customs Notification No. 30/2011 -Customs (ADD) dated 4th March 2011. This circumvention

comes under the category of "product and country circumvention". The Petitioner has submitted that Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd, a branch of Sichuan Weibo New Material Group Co., Ltd (China), was founded in 2012, just after imposition of anti-dumping duty on glass fibre from China PR. Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd produce glass chopped strands mats (CSM, a form of subject goods) from glass roving (AR, also a form of glass fibre) imported from China and then export it to India. Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd is the only glass fibre chopped strand mat unit in Thailand and does not have full-fledged production facilities in Thailand. CSM is the only sub type of glass fibre which requires a two stage processing. Other sub-type of glass fibre attracting anti-dumping duty does not involve two stage processing. Hence, CSM was the only product which could have been processed in Thailand and exported to India. The website of the exporter concerned itself encourages circumvention of anti-dumping duties. The volume of the imports of CSM from Thailand into India has increased and China has declined, since imposition of anti-dumping duty. Also exports of roving from China to Thailand has increased which clearly shows change in pattern of trade since imposition of anti-dumping duty. This circumvention is undermining the remedial effects of the anti-dumping duty imposed on the imports of Glass Fibre originating in or exported from the subject country. Even after the imposition of anti-dumping duty on the imports of Glass Fibre originating in or exported from the subject country, the domestic industry continues to suffer injury on account of circumvention of anti-dumping duty through imports of Chopped Strand Mat (CSM) produced by Asia Composite Materials (Thailand) Co, Thailand.

#### Procedure

7. Having satisfied itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for an anti-circumvention investigation the anti-dumping duty imposed on the imports of glass fibre originating in or exported from the subject country, the Authority has concluded that sufficient *prima facie* evidence exists to initiate an anti-circumvention investigation of the alleged circumvention of the anti-dumping duty imposed on the imports of Glass Fibre originating in or exported from the subject country vide Customs Notification No. 48/2016-Customs (ADD), dated 1<sup>st</sup> September, 2016 in accordance with Section 9A(1A) of the Act, read with Rule 25 of Anti-dumping Rules, to investigate as to whether imports of Chopped Strand Mat (CSM) produced by Asia Composite Materials (Thailand) Co, Thailand are at dumped prices and are causing injury to the domestic industry and the need for extending anti-dumping duty imposed on the imports of Glass Fibre originating in or exported from the subject country vide Customs Notification No. 48/2016-Customs (ADD), dated 1<sup>st</sup> September, 2016 to the imports of Chopped Strand Mat (CSM) produced by Asia Composite Materials (Thailand) Co, Thailand
8. The country involved in this circumvention investigation is Thailand.
9. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is April, 2016 – March, 2017. The injury investigation period will, however, cover the periods April'2013-March'14, April'2014-March'2015, April'2015-March'2016 and the POI.

#### Submission of Information:

10. The known exporter in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product shall be addressed to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

#### The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties

Department of Commerce, Jeevan Tara Building, 4th Floor

5, Parliament Street

New Delhi -110001

11. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out by the Authority. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

#### Time Limits

12. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of communication of initiation of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

13. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the communication of initiation of this Notification.

**Submission of information on confidential basis**

14. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
  - (a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - (b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
15. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.
16. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
17. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
18. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
19. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
20. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

21. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

22. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. Designated Authority